(iii) **राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र**

भा०कृ०अ० परिषद द्वारा गठित किए गए कार्यदल ने सिफारिश की है कि इस केन्द्र की स्थापना निम्न राज्यों में से किसी एक राज्य में की जा सकती है, इन राज्यों के नाम हैं— आध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और असम। प्रस्तावित केन्द्र के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिए एक स्थल चयन समिति बनाई गई है।

(iv) **राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान केन्द्र**

भा०कृ०अ० परिषद द्वारा गठित किए गए कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि इस राष्ट्रीय अनुसधान केन्द्र के लिए गुजरात या राजस्थान उपयुक्त स्थान हैं। भा०कृ०अ० परिषद द्वारा एक स्थान चयन समिति का गठन किया जा रहा है जो इस केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश में एक फल अनुसधान केन्द्र की स्थापना के लिए गयपुर/धार जिले में 500 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव इस राज्य से 1982 में प्राप्त हुआ था। इन राष्ट्रीय अनुसधान केन्द्रो की स्थापना के लिए नियुक्त कार्य दल ने इनमें से किसी भी केन्द्र की स्थापना मध्य प्रदेश में करने की सिफारिश नहीं की है।

Persons employed in Beedi Industry in Tamil Nadu

1876. SHRI V GOPALSAMY
SHRI T R BALU.

Will the Minister of LABOUR be pleased to state

(a) what is the total number of people employed in Beedi Industry in Tamil Nadu;

(b) what is the annual turn over of the Industry; and

(c) what steps are being taken by Central Government for adequate supply of beedi leaves after nationalisation of beedi leaves trade and ban of transport of beedi leaves by Madhya Pradesh Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) The number of beedi workers in Tamil Nadu is estimated to be 2 25 lakhs

(b) According to a Report of an Expert Group on Tobacco, the annual turnover of beedi industry was estimated to be Rs.9,000 crores in 1979.

(c) There is at present no complaint regarding availability of beedi leaves.

Soviet offer for mass transit system in the country

1877 PROF C. LAKSHMANNA. Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Soviet Union has offered to construct a mass transit system like the metro on turnkey basis in the major city of India in the recent visit of Shri Madhavrao Scindia, the Minister of State of Railways to the Soviet Union,

(b) if so, what follow up steps have been taken by the Ministry of Urban Development in this regard as suggested by the Minister of State for Railways; and

(c) what are the details thereof and the cities which are to be covered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) A Protocol signed between Government of India and the Soviet Union in October, 1988 provided, *inter-alia*, that the Soviet side agreed to assist in initiating cooperation in the construction of metro systems in India on a turn-key basis with a suitable financial package In pursuance to this the Soviet Government was requested to send a team of experts to India for discussions on the Metro

system in Delhi. Accordingly, a Soviet Delegation visited India from 11th to 21st February, 1989. It was agreed during the discussion that Government of India will prepare a detailed feasibility report of the East-West Corridor the tentative alignment of which runs from Vivek Vihar in the East to Vikaspur in the West over a distance of around 36 kilometres.

कुछ जिलों में विशेष रोज़गार सुविधायें

1878. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश के कतिपय जिलों में विशेष रोज़गार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है:

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए जिलों अथवा क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं,

(घ) सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय): (क) से (ङ) वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ एक नये गहन ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम की व्यवस्था है जो ऐसे चुने हुए 120 जिलों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा जो पिछड़े हुए हैं तथा जहां अत्यधिक बेरोज़गारी है। इस नये कार्यक्रम के द्वारा ग़रीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोज़गार के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना की निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों को उपलब्ध व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। बजट में इस नये कार्यक्रम के लिए 1989-90 में 500 करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था है।

कीटनाशियों का प्रयोग

1879. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि देश में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशियों का प्रयोग किया जा रहा है:

(ख) यदि हां, तो तीन वर्ष पहले इन कीटनाशी दवाओं के क्षेत्रों में प्रयोग करने की मात्रा क्या थी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कीटनाशियों की कितनी मात्रा का प्रयोग किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सभी कीटनाशी (डी०डी०टी०, बी०एच०सी० और मेलाथिओन) देश में ही उत्पादित किए जाते हैं अथवा उनका आयात किया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार आयात की गई कीटनाशियों की मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) सरकार देश में फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशी दवाइयों का आवश्यकता के आधार पर प्रयोग करने को बढ़ावा दे रही है।

(ख) तीन वर्ष पहले (1985-86) 67,260 मीटरी टन कीटनाशी दवाइयां इस्तेमाल की गई थीं और वर्तमान वित्तीय वर्ष (1988-89) के दौरान तकनीकी ग्रेड की सामग्री के रूप में 86,670 मीटरी टन कीटनाशी दवाइयों की खपत होने का अनन्तिम अनुमान है।

(ग) और (घ) डी०डी०टी०, बी०एच०सी० तथा मेलाथिओन का उत्पादन स्वदेश में ही किया जा रहा है।